



## डिजिटल इंडिया: एक राष्ट्र को जोड़ना

Mr. Dushyantkumar P. Makwana

Assistant Professor

Shri I.J.Patel B.Ed. College, Mogri

Mo. 9558072503, E-mail- [dushyantlimbasi@gmail.com](mailto:dushyantlimbasi@gmail.com)

### सारांश

भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल, विकासशील देशों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों में से एक है। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल का लक्ष्य डिजिटल विभाजन को कम करना, प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन को बेहतर बनाना और डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना है। यह शोध लेख डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से एक राष्ट्र को जोड़ने के अपने मिशन में डिजिटल इंडिया की वैचारिक नींव, कार्यान्वयन रणनीतियों, उपलब्धियों और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। नीतिगत दस्तावेजों, सरकारी रिपोर्टों और द्वितीयक शोध साहित्य की गुणात्मक समीक्षा का उपयोग करते हुए, यह अध्ययन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल साक्षरता, इलेक्ट्रॉनिक शासन और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख स्तंभों की पड़ताल करता है। लेख में भारतनेट, डिजिटल पहचान प्रणाली, मोबाइल कनेक्टिविटी विस्तार, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और सेवा वितरण पोर्टल जैसे प्रमुख घटकों का भी विश्लेषण किया गया है। निष्कर्ष बताते हैं कि हालांकि डिजिटल इंडिया ने कनेक्टिविटी का काफी विस्तार किया है, सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया है और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाया है, फिर भी साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता अंतराल, ग्रामीण-शहरी असमानताओं और अवसंरचना की सीमाओं से संबंधित मुद्दे बने हुए हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि डिजिटल इंडिया ने डिजिटल राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रखी है, लेकिन इसके परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को पूरी तरह साकार करने के लिए निरंतर निवेश, नियामक सुधार और समावेशी क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। यह पहल उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर डिजिटल शासन सुधार के लिए एक वैश्विक केस स्टडी के रूप में सामने आती है।

**मुख्य शब्द:** डिजिटल इंडिया, डिजिटल शासन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, भारत



## प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है। विश्व भर के देश शासन को सुदृढ़ करने, आर्थिक विकास को गति देने और नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का लाभ उठा रहे हैं। इस संदर्भ में, भारत की डिजिटल इंडिया पहल राष्ट्रीय विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की एक व्यापक रणनीति का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2015 को शुरू की गई डिजिटल इंडिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार हो और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़े। इस पहल की परिकल्पना तीन मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है: (क) प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी ढांचा, (ख) मांग पर शासन और सेवाएं, और (ग) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।

अपनी विशाल भौगोलिक विविधता, बड़ी आबादी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण भारत को प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा। 2015 से पहले, डिजिटल पहुंच मुख्य रूप से शहरी केंद्रों तक ही सीमित थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित कनेक्टिविटी और खराब सेवा वितरण तंत्र की समस्या थी। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य एक राष्ट्र को जोड़ने में सक्षम एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके इन असमानताओं को दूर करना था।

यह शोध लेख निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण करता है:

1. डिजिटल इंडिया के मूल घटक और रणनीतिक स्तंभ क्या हैं?
2. डिजिटल इंडिया ने राष्ट्रीय कनेक्टिविटी और शासन सुधार में किस प्रकार योगदान दिया है?
3. इसके पूर्ण कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?
4. सतत डिजिटल राष्ट्र निर्माण के लिए इससे क्या सीख ली जा सकती है?

## ➤ साहित्य समीक्षा

डिजिटल शासन पर विद्वानों की चर्चाएँ पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक भागीदारी बढ़ाने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका पर बल देती हैं। ई-गवर्नेंस मॉडल बताते हैं कि डिजिटल सेवा वितरण से प्रशासनिक लागत कम होती है और जवाबदेही बढ़ती है। विकासशील देशों में, डिजिटल परिवर्तन को अक्सर वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन और मानव पूंजी विकास से जोड़ा जाता है।



भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र पर शोध सेवा वितरण को व्यापक बनाने में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विशेष रूप से पहचान प्रमाणीकरण प्रणालियों और डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के महत्व को उजागर करता है। विद्वानों का तर्क है कि भारत का दृष्टिकोण राज्य-नेतृत्व वाली डिजिटल अवसंरचना को निजी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकृत करता है।

हालांकि, आलोचक डिजिटल बहिष्कार, साइबर सुरक्षा कमजोरियों और असमान डिजिटल साक्षरता स्तरों की ओर इशारा करते हैं। ग्रामीण आबादी, महिलाएं और हाशिए पर रहने वाले समुदाय डिजिटल उपकरणों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार, साहित्य डिजिटल इंडिया को एक परिवर्तनकारी अवसर और एक जटिल शासन चुनौती दोनों के रूप में प्रस्तुत करता है।

### ➤ डिजिटल इंडिया का वैचारिक ढांचा

डिजिटल इंडिया नौ मूलभूत स्तंभों पर आधारित है:

1. ब्रॉडबैंड नेटवर्क
2. मोबाइल कनेक्टिविटी की सार्वभौमिक पहुंच
3. सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम
4. ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
5. ई-क्रांति: सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण
6. सभी के लिए सूचना
7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
8. रोजगार हेतु आईटी
9. प्रारंभिक लाभ कार्यक्रम

ये सभी स्तंभ सामूहिक रूप से एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का लक्ष्य रखते हैं। वैचारिक मॉडल बुनियादी ढांचे के विकास, सेवा एकीकरण और नागरिक सशक्तिकरण पर जोर देता है।

राष्ट्रीय उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना

### ➤ ब्रॉडबैंड विस्तार

तेज़ गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी डिजिटल इंडिया की रीढ़ है। भारतनेट परियोजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों (ग्राम परिषदों) को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करके, यह पहल ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी के अंतर को कम करती है।



## ➤ मोबाइल कनेक्टिविटी

सर्वव्यापी मोबाइल पहुंच ने इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि की है। किफायती स्मार्टफोन और प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजारों ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने में सक्षम बनाया है।

## ➤ डिजिटल पहचान अवसंरचना

बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान प्रणालियों के कार्यान्वयन ने कल्याणकारी योजनाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रमाणीकरण को सक्षम बनाया है। यह अवसंरचना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुगम बनाती है और सब्सिडी वितरण में होने वाले गबन को कम करती है।

## ➤ मांग पर शासन और सेवाएं

डिजिटल इंडिया विभिन्न विभागों में सेवाओं को एकीकृत करके ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को दस्तावेज़ प्राप्त करने, करों का भुगतान करने, लाइसेंस के लिए आवेदन करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

## ➤ डिजिटल भुगतान क्रांति

भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के माध्यम से नकदी रहित लेनदेन की ओर तेजी से बदलाव आया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस, मोबाइल वॉलेट और क्यूआर-आधारित प्रणालियों ने व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए लेनदेन को सरल बना दिया है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान डिजिटल भुगतान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए, जिससे संपर्क रहित वित्तीय लेनदेन और कल्याणकारी योजनाओं का कुशल वितरण सुनिश्चित हुआ।

## ❖ नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण

### ➤ डिजिटल साक्षरता

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक तकनीकी कौशल से लैस करना है। ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक सेवा केंद्र वंचित आबादी को डिजिटल शिक्षा प्रदान करते हैं।

### ➤ सूचना तक पहुंच

सरकारी पोर्टल और ओपन डेटा प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया का एकीकरण सार्वजनिक संस्थानों और नागरिकों के बीच संचार को बेहतर बनाता है।



## ❖ सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

### ➤ वित्तीय समावेशन

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणों ने वित्तीय समावेशन को मजबूत किया है। ग्रामीण परिवारों को अब सरकारी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में मिलती है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।

### ➤ आर्थिक विकास

डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बेहतर डिजिटल अवसंरचना के तहत स्टार्टअप, फिनटेक कंपनियां और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फले-फूले हैं।

### ➤ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा

ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म और टेलीमेडिसिन सेवाएं गुणवत्तापूर्ण संसाधनों तक पहुंच बढ़ाती हैं, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में। डिजिटल रिकॉर्ड स्वास्थ्य सेवा की दक्षता में सुधार करते हैं।

### ➤ चुनौतियाँ और सीमाएँ

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, डिजिटल इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

1. डिजिटल विभाजन: इंटरनेट की गुणवत्ता और सामर्थ्य में लगातार अंतर।
2. साइबर सुरक्षा जोखिम: बढ़ते साइबर खतरों के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता है।
3. डिजिटल साक्षरता में कमी: कई नागरिकों के पास सेवाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल की कमी है।
4. अवसंरचना रखरखाव: ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को बनाए रखना।
5. गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: डेटा प्रबंधन नीतियों में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

दीर्घकालिक स्थिरता के लिए इन मुद्दों का समाधान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

### ➤ तुलनात्मक वैश्विक परिप्रेक्ष्य

भारत का डिजिटल परिवर्तन मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सीख प्रदान करता है। विशुद्ध रूप से बाजार-संचालित मॉडलों के विपरीत, डिजिटल इंडिया राज्य-नेतृत्व वाले बुनियादी ढांचे को निजी नवाचार के साथ एकीकृत करता है। इस पहल का व्यापक विस्तार और समावेशिता इसे एक वैश्विक केस स्टडी बनाती है।



अफ्रीका और दक्षिणपूर्व एशिया के देशों ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के मॉडल का अनुकरण करने के लिए अध्ययन किया है, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान और पहचान प्रणालियों के क्षेत्र में।

### ➤ नीतिगत सिफारिशें

1. साइबर सुरक्षा ढाँचों और डेटा संरक्षण कानूनों को मज़बूत करें।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान का विस्तार करें।
3. अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
4. पहुँच में सुधार के लिए स्थानीय भाषा में उपलब्ध सामग्री को बढ़ावा दें।
5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश करें।

भविष्य की संभावनाएं

डिजिटल इंडिया का भविष्य डिजिटल समावेशन को मजबूत करने और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में निहित है। स्मार्ट शहर, 5जी नेटवर्क, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) अनुप्रयोग कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे।

भारत की डिजिटल परिवर्तन यात्रा यह दर्शाती है कि समन्वित नीति, बुनियादी ढांचे में निवेश और नागरिक भागीदारी किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को गति प्रदान कर सकती है।

### ➤ निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना और समावेशी शासन के माध्यम से राष्ट्र को एकजुट करना है। भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई इस पहल ने ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार किया है, डिजिटल पहचान प्रणालियों को मजबूत किया है, वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया है।

हालांकि साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और अवसंरचना संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, डिजिटल इंडिया ने दीर्घकालिक डिजिटल राष्ट्र निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखी है। इसका डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल समावेशी डिजिटल विकास चाहने वाले अन्य विकासशील देशों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।



जैसे-जैसे भारत तकनीकी नवाचार और नीति सुधारों में निवेश करना जारी रखता है, डिजिटल इंडिया इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को एकजुट कर सकती है और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दे सकती है।

#### ❖ संदर्भ

भारत सरकार। (2015)। डिजिटल इंडिया: सशक्तिकरण की शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। (2023)। डिजिटल इंडिया प्रगति रिपोर्ट।

विश्व बैंक। (2021)। डिजिटल विकास का अवलोकन।

संयुक्त राष्ट्र। (2022)। ई-गवर्नेंस सर्वेक्षण।

